नईदुनिया

संपादकीय

साइबर सुरक्षा में सेंध

डिजिटल होते भारत में जहां जीवनशैली में बदलाव व तरक्की की उम्मीद जगी है, वहीं लगातार हो रहे साइबर हमलों से होने वाले नुकसान ने नीति-नियंताओं की चिंता भी बढ़ा दी है। जिससे आम नागरिकों के खातों में सेंधमारी से हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये की चपत लगाई जाती है। इसी चुनौती के मुकाबले के लिये पिछले दिनों साइबर अपराधियों के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई की गई। पिछले दिनों सीबीआई ने साइबर अपराध के जरिये धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के 76 ठिकानों पर छापे मारे। दरअसल, सीबाआई ने ऑपरेशन चक्र-2 के जरिये उन साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, जो भारतीय नागरिकों के साथ अरबों रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी करने वाले गैंग से जुड़े रहे हैं। दरअसल, यह कार्रवाई वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआईयू द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित थी। उल्लेखनीय है इस बाबत माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अपराधी कॉल सेंटरों के जरिये विदेशी नागरिकों को इन कंपनियों के तकनीकी सहयोगी बताकर शिकार बनाते थे। बताते हैं कि सीबीआई ने इंटरपोल, एफबीआई समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर साइबर अपराधियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस अभियान के तहत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल व दिल्ली आदि में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इससे पता चलता है कि देश के भीतर भी साइबर अपराधियों का जाल किस तरह फैला हुआ है। विडंबना यह है कि विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी से दुनिया में भारत की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध इस बात का भी संकेत है कि अपराधी तकनीकी रूप से दक्षता हासिल करके आक्रामक ढंग से अपने अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिये भी बेहद चिंता की बात है। साथ ही ये साइबर हमले डिजिटल अभियान की सफलता को भी पलीता लगाते हैं।

दरअसल, साइबर अपराधों की चुनौती का मुकाबला करने के लिये जहां सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, वहीं नागरिकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। दरअसल, साइबर अपराधों से निपटने के लिये अनिवार्य दिशा-निर्देशों का सतर्कता से पालन करने, साइबर अपराधियों की निगरानी, साइबर हमले रोकने को पर्याप्त तैयारी की जरूरत है। आये दिन साइबर धोखाधड़ी के तमाम मामले मीडिया में उजागर होते हैं। लोगों की खून-पसीने की कमाई साइबर अपराधी सेकेंडों में उड़ा ले जाते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में मेवात के ग्रामीण इलाकों में एटीएम के जरिये धोखाधड़ी के तमाम मामले प्रकाश में आए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार अभियान को झटका लगा है। अनेक स्थानों पर फर्जी तरीके से नकदी निकासी की घटनाएं पुलिस द्वारा दर्ज की गई हैं। नकदी निकासी के मामले में गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका है। वहीं राजस्थान में भी असुरक्षित स्थानों पर लगे एटीएमों के दुरुपयोग के बाबत बैंकों को अलर्ट किया गया है। एक एडवाइजरी में सीसीटीवी सिस्टम को सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। आईआईटी कानपुर में स्थित गैर-लाभकारी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक दर्ज साइबर अपराधों में से 77.4 फीसदी मामले ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के हैं। जिसको रोकने के लिये सुरक्षा उपायों को बढ़ाने तथा लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया है। दरअसल, साइबर अपराध की दृष्टि से संवेदनशील दस शहरों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के अभाव, सामाजिक-आर्थिक चुनौती तथा कम डिजिटल साक्षरता के चलते ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। दरअसल, अपराध से लड़ने के सामान्य तौर-तरीकों से साइबर अपराधों का मुकाबला नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भोले-भाले नागरिकों को धोखा देने के लगातार नये-नये तरीके विकसित कर रहे हैं। नागरिकों को जागरूक करके तथा सुरक्षा के पेशेवर परामर्श से इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों, व्यवसायियों व नीति-निर्माताओं के बेहतर तालमेल से इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा के गौरवशाली 98 वर्ष

दृष्टिकोण

-बृजनंदन राजू

हिंदू संगठन और राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के जिस उद्देश्य को लेकर सन् 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, उस ध्येय पथ पर संघ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। संघ अपनी विकास यात्रा के 98 वर्ष पूर्ण कर चुका है। उपेक्षा व विरोध का सतत सामना करते हुए अत्यंत विपरीत परिस्थितियों से पार पाते हुए संघ कार्य आज अनुकूलता की स्थिति में पहुंचा है। इन 98 वर्षों की यात्रा में हिन्दू संगठन के साथ-साथ आम लोगों का विश्वास जीतने और राष्ट्र जागरण के प्रयास में संघ पूर्णतया सफल रहा है। देश दुनिया में आरएसएस नाम से विख्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। संघ की तुलना किसी दूसरे संगठन से नहीं कर सकते क्योंकि तुलना करने के लिए भी इसके जैसा कोई होना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग स्वार्थवश संघ को बुरा-भला कहते हैं। कुछ लोग अज्ञानवश भी संघ की आलोचना करते हैं क्योंकि उनको संघ की असलियत पता नहीं है।

नागपुर से शुरू हुआ संघ विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इस वटवृक्ष की छांव में भारत की संस्कृति और परम्परा पुष्पित पल्लवित हो रही है। आज 50 से अधिक संगठन विविध क्षेत्रों में संघ से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। यह सभी संगठन स्वायत्त जरूर हैं लेकिन उनके पीछे संघ की शक्ति ही सक्रिय है। विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाले संघ के आनुषांगिक संगठन विश्व के शीर्ष संगठनों में शुमार हैं। चाहे किसान संघ हो, मजदूर संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, वनवासी बंधुओं के बीच कार्य करने वाला संगठन वनवासी कल्याण आश्रम हो, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती,धर्म के क्षेत्र में सक्रिय विश्व हिन्दू परिषद हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी। यह सब विश्व में चोटी के संगठन हैं। भाजपा की आज केन्द्र समेत देश के कई राज्यों में सरकार है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर संघ के स्वयंसेवक विराजमान हैं। इसलिए भी आज संघ के बारे में जानने को देश दुनिया में उत्सुकता बढ़ी है।

किसी भी संगठन के बारे में जानने से पहले उस संगठन को शुरू करने वाले व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए यदि संघ को जानना है तो डॉ. हेडगेवार के जीवन के बारे में जानना होगा। उनके जीवन को समझे बिना संघ को नहीं समझा जा सकता। डॉ. हेडगेवार क्रान्तिकारी थे। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान कलकत्ता में उनका क्रान्तिकारियों से संपर्क हुआ। पढ़ाई पूरी कर जब वह वापस नागपुर आये तो कांग्रेस में सक्रिय हो गये। कठोर परिश्रम, मितव्यी व्यवहार के कारण शीघ्र ही वह कांग्रेस में प्रान्तीय स्तर के नेता बन गये। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ चुका था। तिलक की मृत्यु के पहले ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभक्त हो चुकी थी। क्रान्तिकारी अंग्रेजों की नाक में दम किये थे। कांग्रेस में तुष्टीकरण की नीति हावी हो रही थी। मुस्लिम कांग्रेसी वंदेमातरम गाने से इनकार कर रहे थे जबकि गांधी जी ने मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए देश में खिलाफत आन्दोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आन्दोलन का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से कोई मतलब नहीं था। तुर्की के खलीफा को उसकी गद्दी से हटा देने के बाद भारत के मुसलमानों ने इस आन्दोलन को शुरू किया था। आन्दोलन असफल हो गया। क्योंकि तुर्की के मुसलमान स्वयं खलीफा नहीं चाहते थे। आन्दोलन असफल होने से भारत में इसका उल्टा परिणाम हुआ। उन्होंने उल्टे हिन्दुओं पर हमले करने शुरू कर दिये। मोपला विद्रोह हुआ। इन सब घटनाओं का डॉ. हेडगेवार ने बारीकी से अध्ययन किया। उस समय की परिस्थिति को देखकर यह लग रहा था कि भारत जल्द आजाद होने वाला है। लेकिन आजादी के बाद देश का भविष्य क्या होगा इस बारे में स्पष्ट कल्पना लोगों के दिमाग में नहीं थी। डॉ. हेडगेवार ने सोचा आजादी तो हमें मिल जायेगी लेकिन क्या गारंटी है कि भारत दुबारा गुलाम नहीं होगा। उन्होंने भारत की गुलामी के कारणों का अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि भारत धनधान्य से परिपूर्ण था,बड़े -बड़े शूरवीर योद्धा, उन्नत हथियार सारे संसाधन भारत में मौजूद थे। कमी एक चीज की थी कि स्वत्व का अभाव था। यहां का समाज आपस में जातियों में बंटा था। तब ध्यान में आया कि अगर हम एक नहीं हुए तो हम पिटते रहेंगे लुटते रहेंगे और गुलाम बनते रहेंगे। डॉ. हेडगेवार ने निश्चय किया कि हम एक ऐसा संगठन बनायेंगे जिससे जुड़े युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना, भारत की परम्परा और संस्कृति के प्रति अनुराग और गौरव का भाव होगा। इस महान कार्य के लिए उन्होंने बच्चों को चुना। वह बच्चों के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते और उनसे भी सुनते। शाखा शुरू हुई। धीरे-धीरे कार्यपद्धति का विकास हुआ। दायित्व का नामकरण, आज्ञा, प्रार्थना और गुरू दक्षिणा शुरू हुई।

देशकाल परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र रक्षा के स्वरूप और प्रक्रिया में बदल आता रहता है। कोई भी संगठन समय और परिस्थिति के अनुसार अगर बदल नहीं करता है तो उसकी स्वीकार्यता समाप्त हो जाती है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज कितना बड़ा संगठन था आज उनकी संपत्तियों को देखने वाला कोई नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी करीब उसी कालखण्ड में हुई थी आज समाप्ति की ओर है। इसलिए डॉ. हेडगेवार ने शाखा रूपी अनोखी कार्य पद्धति विकसित की। शाखा में नित्य जाना होता है। जबकि देश दुनिया के किसी संगठन में नित्य मिलन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति नजदीक की संघ शाखा में जाकर संघ में सम्मिलित हो सकता है। उसके लिए कोई भी शुल्क या पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीब 70 हजार शाखाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का अहर्निश कार्य कर रहा है। उपेक्षा,उपहास,विरोध सहते हुए तथा अनेक झंझावातों को पार करते हुए संघ कार्य आज निरंतर बढ़ रहा है।

बिखर तो नहीं जाएगा इंडिया गठबंधन..!

मुद्दा

-विनीत नारायण

आगामी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी दल की जो बयानबाजी हुई हैं, वो 'इंडिया' गठबंधन के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो कड़ी मेहनत की है, उससे हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है।

जब से पटना, बेंगलुरु और मुंबई में प्रमुख विपक्षी दलों की महत्त्वपूर्ण बैठकें हुई और 'इंडिया' गठबंधन की घोषणा हुई तब से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी क्योंकि पिछले नौ वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा विपक्षी दलों पर हावी रही है। पर पिछले दिनों 'इंडिया' गठबंधन में शामिल कुछ दलों के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर ऐसी तीखी टिप्पणियां की हैं, जिससे गठबंधन में दरार पड़ सकती है।

आगामी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी दल की जो बयानबाजी हुई हैं, वो 'इंडिया' गठबंधन के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो कड़ी मेहनत की है, उससे हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है। शायद इसी आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की कोई अहमियत नजर नहीं आई पर अगर यही रवैया रहा तो लोक सभा के चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन कैसे मजबूती से लड़ पाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दल तीसरी बार भी नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान कर देंगे पिछले नौ वर्षों में विपक्ष ने तमाम हमले सत्तारूढ़ दल पर किए पर फिर भी कामयाबी नहीं मिली।

ज्यादातर हमले प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक घोषणाओं, नीतियों और कार्यपणाली पर हुए। जैसे मोदी की 2014 की घोषणाओं को याद दिलाना कि दो करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेगी, कि 2022 तक सबको पक्के घर मिलने का वादा क्या हुआ कि 15 लाख सबके खातों में कब आएंगे कि सौ स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई कि मां गंगा मैली की मैली क्यों रह गई कि विदेशों से काला धन वापस क्यों नहीं आया इसके अलावा, मोदी के अडाणी समूह से संबंधों को लेकर भी संसद में और बाहर बार-बार सवाल पूछे गए। आम आदमी पार्टी ने मोदी की डिग्रियों को लेकर सवाल खड़े किए। आरबीआई की जानकारी के अनुसार पिछले नौ वर्षों में बैंकों का 25 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में चला गया। आम जनता के खून-पसीने की कमाई की ऐसी बर्बादी और लाखों करोड़ रुपये के ऋण लेकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी जैसे लोगों के बारे में भी सवाल पूछे गए। मोदी सरकार पर सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इन एजेंसियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ इकतरफा कार्रवाई और चुनावों के पहले उन पर छापे और गिरफ्तारियों को लेकर भी पूरा विपक्ष उत्तेजित रहा। किसान आंदोलन की उपेक्षा और सैकड़ों किसानों की शहादत और गृह राज्य मंत्री के बेटे का लखीमपुर में आंदोलनकारी किसानों पर कातिलाना हमला भी मोदी सरकार पर हमले का सबब बना। ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों पर मोदी सरकार की चुप्पी और बाद में उन्हें पुलिस के जोर पर धरने से हटाने को लेकर भी सरकार की बार-बार खिंचाई की गई। मणिपुर में भारी हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री का महीनों तक वहां न जाना भी बड़े विवाद का कारण बना है। ऐसे तमाम गंभीर सवालों पर प्रधानमंत्री का लगातार चुप रह जाना और एक बार भी संवाददाता सम्मेलन न करना लोकतंत्र के करोड़ों मतदाताओं को आज तक समझ में नहीं आया।

उधर हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का आक्रामक प्रचार और विपक्षियों को भ्रष्ट बता कर हमला करना जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री द्वारा ही बार-बार भ्रष्ट बताए गए विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल करवा कर उनके साथ सत्ता में भागीदारी करना भी बड़े विवाद का कारण रहा है। इस सब से देश में ऐसा माहौल बना कि विपक्ष इसे अघोषित आपातकाल कहने लगा किंतु स्थानीय राजनीति पर अपनी पकड़ छोड़ने को कोई क्षेत्रीय दल तैयार न था। इसलिए विपक्ष के दल जहां भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करने से भी बाज नहीं आए। यही कारण है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के समर्थन का दावा करने वाले विपक्ष के नेता अपने-अपने क्षेत्रों में तो कामयाब हुए पर राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पाए। आज भी जनाधार वाले तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए केंद्र में सत्ता पाने का उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।

विपक्ष को इस अंधकार से निकालने की पहल कुछ प्रांतीय नेताओं ने की और उनके प्रयास से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनीं। दूसरा काम 'भारत जोड़ो यात्रा' के माध्यम से राहुल गांधी ने किया।

जिन राहुल को भाजपा और संघ परिवार ने 'पप्पू' सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हीं राहुल ने 'भारत जोड़ो यात्रा' में हर आम आदमी को गले लगा कर अपनी छवि में चार चांद लगा दिए। मीडिया से डरे बिना हर दिन सैकड़ों संवाददाताओं के तीखे सवालों के सहजता से उत्तर दिए। संसद में मोदी सरकार पर इतना कड़ा हमला बोला कि उनकी सांसदी ही खतरे में पड़ गई पर राहुल के इस नये तेवर और कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत ने राहुल गांधी को ऐसे आत्मविश्वास से भर दिया कि वे बांहें फैला कर हर विपक्षी दल को 'इंडिया' गठबंधन में जोड़ सके। इसी से भारतीय लोकतंत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ पर जिस जोर-शोर से 'इंडिया' गठबंधन की घोषणा हुई थी, वो गर्मी अब धीरे-धीरे शांत होती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। पिछले दिनों 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो हमला बोला उससे गठबंधन में दरार पड़ने का संदेश गया। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा वादा करने के बावजूद सपा को 5-7 टिकटें नहीं दी गई। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई।

आजकल

दिल्ली में फिर ज़हरीली हवा

हर साल की तरह सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को फिर घातक प्रदूषण की चादर ने अपनी चपेट में ले लिया है। फिर से वायु गुणवत्ता का अत्यंत खराब श्रेणी में आना नागरिकों की चिंता बढ़ाने वाला है। एक्यूआई का तीन सौ पार करना इसका ज्वलंत उदाहरण है जो बताता है कि गाल बजाती राजनीति इस संकट के मूल का उपचार करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थितियां हर साल आती हैं कभी ठीकरा पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के सिर फोड़ दिया जाता है। कभी दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार कह दिया जाता है। लेकिन हमारी जीवनशैली की खामियों पर चर्चा नहीं होती। दरअसल, हर साल इन दिनों तापमान में गिरावट आने व हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषकों को जमा होने का मौका मिल जाता है। दरअसल, मूल बात यह है कि बेहद तेजी से हुए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से हवा के मूल प्रवाह मार्ग में अवरोध पैदा हो गया है। यह प्रदूषण सिर्फ पराली का नहीं है। बदले लाइफ स्टाइल के चलते हर घर में कई-कई कारें रखने से भी प्रदूषण में इजाफा हुआ है।

हमारे नीति-नियंताओं का सबसे बड़े दोष यह है कि वे सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को इतना सहज-सरल ढंग से उपलब्ध नहीं करा पाये कि लोग कार सड़कों पर उतारने के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। फिर नीति-नियंता उस सनातन मानसिकता से ग्रसित हैं जो आग लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति से युक्त होती है। हर बार जब संकट सिर पर आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाता है कि दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गया, तब दिल्ली सरकार सक्रियता दिखाती है। दरअसल, जो कार्रवाई होती भी है वह प्रतीकात्मक होती है। मीडिया के जरिये ये दिखाने का प्रयास होता है कि सरकार भाग-दौड़ कर समस्या का समाधान करने को तत्पर है। लेकिन जैसे ही बारिश होने या हवा के रुख में बदलाव से स्थिति में सुधार होता है, सरकार भी शिथिल हो जाती है।

दरअसल, दिल्ली के प्रदूषण संकट को समग्र रूप से संबोधित करने की जरूरत है। उन तमाम कारणों पर विचार करने की जरूरत है जो इस संकट के मूल में हैं। ये कारण हमारे निर्माण कार्य में लापरवाही, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम, अनियोजित विकास और लगातार बढ़ते जनसंख्या घनत्व में तलाशे जाने चाहिए।

विधानसभा चुनावों की तपन और रुख बदलती सियासी पवन

राजनीति

-ऋतुपर्ण दवे

पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह से उठापटक का नजारा दिख रहा है वो नया नहीं है। लेकिन नवंबर-2023 में होने जा रहे पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव जरूर तमाम रणनीतिक गतिविधियों के चलते अलग नजर आ रहे हैं। जिस रास्ते भाजपा और काँग्रेस चल रही है वह खुद बड़ा संकेत है। भाजपा ने भले मध्य प्रदेश से बेहद पुरानी शुरुआत को नए लिबास में कर तीनों अहम हिन्दी पट्टी राज्यों में भी प्रयोग दोहरा, मौजूदा सांसदों या केन्द्रीय मंत्रियों को जंग में उतार तमाम दिग्गजों सहित खुद भाजपाइयों को अचरज में डाल दिया। इसकी खबर प्रत्याशी के सिवाय किसी को कानों कान नहीं थी। इसी तरह काँग्रेस ने भी भाजपा से आए लोगों को टिकट देने में गुरेज न कर बड़ा दाँव खेला है। अब दोनों ही दल कार्यकर्ताओं के विरोध को झेल रहे हैं। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा।

ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपनी महीन चुनावी रणनीति के तहत सांसदों व मंत्रियों को मैदान में उतारा है। यह बहुत सोची, समझी, सधी हुई चाल है जिसमें एक साथ कई-कई संदेश छिपे हैं। परिस्थितियों वश भाजपा किसे आगे करे, किसे मुखौटा बनाए के बजाए सबको आपस में उलझाए रखने जैसी रणनीति अपना रही है जो कहीं न कहीं छिपा डैमेज कंट्रोल तो नहीं मध्य प्रदेश में भाजपा उदारवादी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज का चेहरा सामने रखने में सत्ता विरोधी लहर और दूसरे अन्दरूनी डर से भले डरी हो लेकिन काँग्रेस अभी भी संगठनात्मक रूप से यहाँ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जो होना था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार, संगठन व लोकप्रियता में भाजपा को जरूर बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विजयाराजे सिंधिया के वजूद और सचिन पायलट की हां-ना के बीच पशोपेश की स्थिति से लगता है कि वहाँ भी दोनों दलों में आंतरिक चुनौतियां कम नहीं हैं। राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा चुनौती भाजपा में हैं। हाल ही में सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज अब टूटेगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर जैसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। हो सकता है कि यहां काँग्रेस 2018 के मुकाबले और सुधार करे। यहां भी भाजपा ने कई मौजूदा सांसदों और केन्द्रीय मंत्रियों को विधानसभा टिकट देकर जो प्रयोग किया है उसके नतीजों पर सबकी निगाहें होंगी। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच है। टीडीपी और एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। मिजोरम में मुकाबला एमएनएफ, जेडपीएम, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा।

टिकट वितरण में बड़े चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाने के साथ दूसरे दलों से आकर टिकट हथियाने वालों से साधारण कार्यकर्ताओं में भले ही जबरदस्त असंतोष दिखे। लेकिन इससे हवा के रुख पर फर्क जरूर दिख रहा है। भाजपा और काँग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कम से कम हिन्दी पट्टी क्षेत्रों में स्थिति टिकट वितरण के पहले और अब काफी बदली हुई लग रही है। विरोध के स्वर और नेताओं के उवाच लोगों को हैरान कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कथित मीठी नोंक-झोंक जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है उसे मप्र में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी पैराशूट खासकर कांग्रेस से आए प्रत्याशियों को लेकर भीतर ही भीतर सुलग रही अंतर्विरोध की आग बुझेगी या बढ़ेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर बसपा, सपा और आप की मौजूदगी भाजपा से ज्यादा काँग्रेस के लिए बड़ी चुनौती जरूर बनती दिख रही है। ये तीनों ही दल ज्यादातर काँग्रेस के वोट बैंक को ही चोट पहुंचाते नजर आ रहे हैं।

चुनावी रण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है कहना अभी जल्दबाजी होगी। टिकटों खुलासे से पहले जहां हवा का रुख कुछ अलग था वो अब अलग है। पहले मप्र व राजस्थान में कांग्रेस खेमा सत्ता के सिंहासन को बेहद भरोसे से करीब देख रहा था। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर थोड़ा सशंकित है। हवा कुछ प्रदूषित सी लगने लगी है। पहले घर बैठे जीत का मन बना चुके प्रत्याशी भी कार्यकर्ताओं के घरों पर याचक बन दस्तक देते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर, पन्ना प्रमुख, वार्ड प्रभारी, बूथ कार्यकर्ताओं, सेक्टर प्रभारियों की सूची को बार-बार क्लिक करते दिख रही है। काँग्रेस के पास अपने पुराने बरसों पुराने कार्यकर्ताओं का ही भरोसा है। इन्हीं के दम पर बीते बरस स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान भी काँग्रेस ने खासा दमखम दिखाया था। कहीं जीतकर भी हारे तो कहीं हारकर भी जीते जैसी स्थितियों से काफी हंसी हुई थी। इन्हीं उधेड़बुन के बीच जो तस्वीरें मध्यप्रदेश से आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। कमलनाथ के घर के सामने आत्मदाह की कोशिश तो पंगत बिठा सार्वजनिक भोज कराने का अलग नजारा रहा। सेवड़ा, जावरा, मलहरा, डॉ.आंबेडकर नगर(महू), खरगापुर, निवाड़ी, सोहागपुर, शुजालपुर, गोविंदपुरा, बैरसिया, बड़नगर, खातेगांव, गोटेगांव सहित कुछ अन्य सीटों के प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है।